delivery of Health Care services in these centres is the sole responsibility of State/U.T. Governments.

There is no proposal for independent monitoring or evaluation of P.H.Cs. for the time being. However, during the Eighth Five Year Plan the main thrust would be to consolidate the health centres already established in the States/U.Ts., so that effective services are provided to the rural population.

Marketing of 'SELECT' Capsules

587. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that M/s. Vasu Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Vadodara are advertisting and marketing a capsule calles "SELECT" claiming that only male children are borne by taking this capsule;

(b) whether Government have permitted the manufacture and advertisement of this product after due testing and if so, the details of trials conduced; and

(c) if not, whether Government propose to take suitable corrective steps in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI DASAI CHOWDHARY): (a) to (c) Food and Drugs administration, Gujarat States Government had earlier permitted M/s. Vasu Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Baroda to manufacture 'Select' A & B Capsules as Ayurvedic medicines.

Food and Drugs Administration Gujarat has since withdrawn the permission. The manufacturer has stopped the production.

केंद्रीय संस्कृत मंडल की बैठकें

588. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय संस्कृत मंडल की बैठकें कब-कब हुई हैं इसकी अगली बैठक कब होने वाली है ; और

(ख) इन बैठकों में केन्द्रीय संस्कृत मंडल ने अपने अध्यक्ष के निर्देशन में क्या-क्या सुझाव दिये थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय) : (क) केन्द्रीय संस्कृत मंडल (सेंट्रल संस्कृत बोर्ड) की गत बैठकें 17 जुलाई, 1984, 17 जनवरी, 1986, 4 जुलाई, 1989, 15 सितम्बर 1989 व पहली सितम्बर, 1990 को आयोजित की गयी थीं। अगली बैठक की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) इन बैठकों में केन्द्रीय संस्कृत मंडल द्वारा दिये गये सुझावों व उन पर की गयी कार्रवाई से संबंधित विवरण साथ में संलग्न हैं।

विवरण

केन्द्रीय संस्कृत मंडल द्वारा दिए गए सुझाव तथा उन पर की गई कार्यवाही

सुझाव	की गई कार्यवाही
1. श्रीलाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली व केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को विश्वविद्यालयवत के रूप में घोषित करना।	1. दोनो केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठों को पहले ही 1987 में विश्वविद्यालय समझे जाने वाला संस्थान घोषित कर दिया गया है।

सुझाव	की गई कार्यवाही
2. वैदिक प्रतिष्ठान की स्थापना।	2. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना सन 1987 में नई दिल्ली में की गयी है ।
3. भारत के संस्कृत संस्थानों की निदेशिका प्रकाशित करना ।	3. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को भारत में संस्कृत" नामक निदेशिका तैयार करने का कार्य सौंपा गया है और इस कार्य का अधिकांश महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया गया है ।
4. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना	4 श्रंगेरी (कर्नाटक) में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचराधीन है ।
5. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में घोषित करना ।	5. सरकार ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के कुलाधिपति श्री टी० एन० चतुर्वेदी की अध्यक्षता में प्रख्यात संस्कृत विद्वानों प्रशासकों की एक समिति गठित की है । यह समिति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सांविधिक आयोग का स्तर प्रदत्त करने के प्रश्न सहित प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करेगी ।
6. पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं में पढ रहे संस्कृत छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि बढाना ।	9. केंद्रीय संस्कृत मंडल की सिफ़ारिशें, सरकार के पास विचराधीन हैं ।
7. चरित्रा तेलुगु व तमिल साहित्य का संस्कृत में अनुवाद ।	7. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को यह कार्य सौंपा गया है ।
8. केंद्रीय संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना ।	8. श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (अब विश्व विद्यालयवत) से पूछा गया है कि क्या प्रस्तावित केंद्रीय संस्कृत पुस्तकालय को उसके परिसर में स्थापित किया का सकता है ।
9. स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के शिक्षण को उचित स्तर प्रदान करना	9. मामला न्यायाधीन है और स्कूली शिक्षा में संस्कृत के शिक्षण के संबंध में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार यथापूर्व स्थिति रखी जा रही है ।
10. संस्कृत शिक्षा में लगे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों का सर्वेक्षण ।	10. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली से अध्ययन कार्य को पूर्ण करने में तेजी लाने को कहा गय है लेकिन कार्य कठिन है क्योंकि अधिकांश संस्कृत संस्थानों के पास अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों का न तो वर्तमान पता है और न ही उनके रोजगार स्तर की जानकारी है ।